

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

ने खाद उधार ले लिया था, बीज उधार ले लिया था। आज यह जरूरी हो गया है कि सरकार उन लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाए जिससे कि वे फसल बो सकें। नहीं तो वे अगली गर्मी की फसल नहीं बो पायेंगे। इसलिए सरकार को उन लोगों की अधिक से अधिक सहायता करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उन लोगों के लिए राहत कार्य भी तत्काल शुरू करने की जरूरत है। इस क्षति में वहां के खेतिहर मजदूरों के पास ऋण शक्ति नहीं रही है। उन्हें गल्ले पहुंचाने की जरूरत है जिससे वे अपना जीवन बचा सकें। मध्य प्रदेश के कई जिलों—सीहोर, विदिशा, दमोह, सागर, रायसेन, सतना, रीवा—में इस ओला वृष्टि से क्षति हुई है। अकाल एरिया घोषित कर तत्काल सहायता की जाये। वहां की जनता का कष्ट दूर हो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त उनकी सहायता करे और जो संकट आया है वह दूर हो सके, इसके उपाय करे।

(v) NEED FOR CENTRAL ASSISTANCE TO
MADHYA PRADESH TO MEET THE SITUATION
ARISING OUT OF HEAVY RAINS

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : इसी प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान दिलाते हुए आगे की कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। वहां पर असमय वर्षा हुई है, बहुत हुई है। जबलपुर और सिवनी जिले में 85 इंच तक वर्षा इस बार हुई है। उसके कारण दो-दो बार दौर्भाग्य करनी पड़ीगी किसानों को। दो बार करने के बाद जब फसल लहलहा रही थी तब ओला-वृष्टि हो गई और जबलपुर और सिवनी तथा मध्य भारत के बहुत से जिले उससे प्रभावित हुए और उसने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार को 35 करोड़ रुपया राहत कार्यों पर खर्च करना पड़ा था जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने केवल पांच करोड़ दिया और तीस करोड़ उसे अपने खाते से खर्च करना पड़ा। अब जो राहत कार्य हाथ में लिए जाएंगे उनमें मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अंशदान दें। इस बात की बहुत आवश्यकता है कि तकाबी की जो वसूली की जा रही है उसे तुरन्त निरस्त कर दिया जाए। बैंक लॉज पर जो ब्याज है वह माफ कर दिया जाना चाहिए। बैंकों की तरफ से किसानों से आगे कर्जा वसूल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आदेश तो कम से कम केन्द्रीय सरकार उनके दे ही सकती है।

वहां इस समय फसल विल्कुल चौपट हो चुकी है। अन्न तथा धान से तत्काल मध्य प्रदेश को इस संकट की घड़ी में सहायता की जानी चाहिए। उसी तत्परता के साथ सहायता की जानी चाहिए जिस तत्परता के साथ आंध्र और तमिलनाडु में हुई क्षति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने सहायता की थी। उसी तत्परता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्र की ओर से अंशदान भी दिया जाए और अन्न सहायता भी प्रदान की जाए।

12.40 hrs.

INTEREST BILL—contd.

MR. SPEAKER: Now, we take up next item. Mr. Patel....

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Sir.....

MR. SPEAKER: Mr. Venkataraman, you want to object to it at this stage?